# मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से जनसुनवाई बनी सुशासन की नई मिसाल

## मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। शासन को सेवा का माध्यम मानते हुए यह सरकार

- जयराम और कैलाश को मिला कृषि विद्युत कनेक्शन
- मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद, अब नहीं सूख रही फसलें

प्रदेशवासियों के हित के लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई भी इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में समस्या का समाधान किया।

जनसुनवाई में फरियादी नगर निगम, जेडीए, गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। कोई परिवादी बीमारी में इलाज की मदद के लिए आते हैं तो कोई परिवादी अपनी पेंशन से जुड़े प्रकरण को निस्तारण के लिए तो कोई विद्युत कृषि कनेक्शन के लिए। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

कोटपूतली के नारायणपुर तहसील निवासी जयराम किसान परिवार से हैं। उन्होंने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जोकि पिछले काफी समय से लंबित था। जनसुनवाई में अपने इस प्रकरण को लेकर जब जयराम आए तो मुख्यमंत्री ने फसलों के सीजन को देखते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जयराम के कृषि कनेक्शन आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसी तरह अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के कैलाश चंद मीणा को भी कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में फसलों की सिंचाई नहीं होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को अपनी इस परेशानी से अवगत कराया।

# नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा व स्टाफिंग में खामियों को लेकर नोटिस जारी

## आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी

**जयपुर/जोधपुर।** राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा शामिल हैं, ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा, स्टाफिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नवोदय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत आर. दवे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कई नवोदय विद्यालयों में अब तक पूर्णकालिक वार्डन, काउंसलर, सीसीटीवी निगरानी, परिधि सुरक्षा, आपात प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनसीपीसीआर, एनडीएमए द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई चौंकाने वाले तथ्य को उजागर

- जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े है
- विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे अधारभूत ढ़ांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है

किया है जैसे कि दिसम्बर 2024 की शिक्षा के क्षेत्र में संसद की स्थासी समिति को भी उद्धृत किया है जिसके अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े है। यानी इन विद्यालयों में 24.77 प्रतिशत पदो की रिक्तियों को भरा नही गया है जबकि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि रिक्तियों को जल्द भरा जाये। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2019 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को एमटीएस के रूप में छात्रावासों की देखरेख के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जो केवल औपचारिकता रह गया है और योग्यता आधारित स्टाफिंग के मापदंडों का उल्लंघन करता है।

इसके अतिरिक्त, याचिका में यह भी ज़ोर दिया गया है कि विगत वर्षों में नवोदय विद्यालयों में आत्महत्याओं सहित कई छात्र मौतों की घटनाएं सामने आई हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और छात्रावासों में अपर्याप्त निगरानी की ओर इशारा करती हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी। आरटीआई से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के बिच ही इन विद्यालयों में 49 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें से आधे एसएसी -एसटी वर्ग के थे। वही 2019 से 2023 के बीच 25 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा एसएसी -एसटी वर्ग का था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्यादातर इन मौतों में कई मामलों में एफआईआर दर्ज है परन्तु कई मामलों में मौत का कारण स्पष्ट नही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात से नकारा नही जा सकता कि इन विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे अधारभूत ढ़ांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है, और आये दिन इन मुदो पर प्रदर्शन किये जाते हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।

# कुमावत को एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाने पर मांगा जवाब

**जयपुर।** राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, आरसीए और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता मधुसुदन सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता क्रिकेट संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को साल 2022 से 2026 के लिए चुना गया था। दीनदयाल कुमावत अपने आप को सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अन्य याचिका लंबित है। याचिका में कहा गया कि सहकारिता विभाग ने गत 27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लडने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं। वे सवाई माधोपुर के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं है। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

# विवाद बढ़ा तो ठेकेदारों ने 20 प्रतिशत रेट घटाकर ले लिया पौधे सप्लाई का टैंडर

**- कार्यालय संवाददाता-**

**जयपुर।** ग्रेटर निगम में पौधे सप्लाई के टैंडर में भारी गड़बड़झाला चल रहा हैं। ''वन टाइम प्लांटेशन'' के लिए 10 फ़ीट पौधे देने के लिए ठेकेदारों ने पहले तो मात्र 5 प्रतिशत कम रेट डाली थी, परन्तु हैरिटेज निगम में 55 प्रतिशत कम दर आने के बाद जब विवाद बढ़ा तो इन्ही फर्मों ने अपनी रेट 20 प्रतिशत तक घटाकर काम ले लिया।

अब चर्चाएं यह हो रही है कि आखिर हैरिटेज निगम से 35 फ़ीसदी ज्यादा कीमत पर पौधे खरीदने के लिए ग्रेटर निगम के अफसर उत्सुक क्यों है? वह भी उस स्थिति में जब अधिकांश ठेके एक ही फर्म मैसर्स जसवाल बिल्डर्स के नाम पर छूटे है। हालाँकि उद्यान शाखा के अफसरों का कहना है कि 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर पौधे उपलब्ध करवाना संभव ही नहीं है। परन्तु सवाल यह उठ रहा है कि यह चिंता तो कम दर पर ठेके लेने वाले संवेदक को होनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर निगम प्रशासन ने वन टाइम प्लांटेशन कि निविदा के कार्यादेश ''नेगोशिएशन'' के बाद 20 प्रतिशत कम दर पर जारी किये है। यहाँ ठेकेदार ने 300 रुपए के 10 फीट के पेड़ 270 से 285 रुपए तक में देने की दर डाली थी, परन्तु जब हैरिटेज निगम में आधी कीमत यानी कि 135 से 150 रुपए तक की रेट आयी तो बड़ा विवाद हो गया। तमाम विवादों के बावजूद ग्रेटर निगम प्रशासन ने यह कार्यादेश जारी करने का फैसला लिया। मजेदार बात यह है कि जेडीए प्रशासन ने भी यही पेड़ ठेकेदारों से 160 से 170 रुपए के बीच खरीदे है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे है कि आखिर ग्रेटर निगम प्रशासन ही जानबूझकर लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान क्यों झेलने पर उतारू है। जबकि तीनों विभागों ने पौधों की एक समान खरीद दर 300 रुपए तय की थी। जिसमें नीम, शीशम, करंज, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, चंपा, आंवला, सीताफल, खेजड़ी, अर्जुन, बालम खेड़ा, कनेर, हरसिंगार, शहतूत, अमरूद, पीपल, जामुन, बेलपत्र, गुड़हल, मौलश्री, चंदन और आम के पेड़ शामिल है।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर नगर निगम की उद्यान शाखा ने इस बार ''वन टाइम प्लांटेशन'' के 30 लाख रुपए से कम के टेंडर में भी कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थी, जिसके कारण ''डी'' श्रेणी के ठेकेदार चाहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस कारण इन निविदाओं में सिर्फ चुनिंदा फर्मों ने ही भाग लिया।

# भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करे सरकार

**जयपुर।** राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून की समीक्षा करे और जरूरत पडने पर उन्हें संशोधित करने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अनूठी परिस्थिति में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेहर गोगिया के अपने पिता के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निर्वासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
- याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निर्वासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निर्वासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि उसके माता-पिता का मार्च, 2018 में विवाह हुआ था। इसके बाद वे आस्ट्रेलिया गए थे। जहां 1 जून, 2020 को याचिकाकर्ता का जन्म हुआ। इस पर वहां की सरकार ने नवंबर, 2021 में याचिकाकर्ता को नागरिकता दे दी। इसके बाद वह भारत सरकार से वीजा लेकर अपने माता-पिता के साथ यहां आ गई। इस दौरान उसकी समय-समय पर वीजा अवधि 24 जनवरी, 2024 तक बढ़ाई गई। याचिका में कहा गया कि इस बीच याचिकाकर्ता के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद पैदा हो गया और उसकी मां ने याचिकाकर्ता के पिता पर कई केस कर दिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इमिग्रेशन ब्यूरो में याचिकाकर्ता की वीजा अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसे ब्यूरो ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी मां ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसे अवैध प्रवासी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मामले में कोर्ट दखल देकर उसकी वीजा अवधि बढाए। इसका विरोध करते हुए इमिग्रेशन ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से अभी तक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या उसे डिपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता आस्ट्रेलिया की नागरिक है और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।

# देवनानी ने लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की

**जयपुर।** राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को नई दिल्ली की एक दिवसीय यात्रा के दौरान संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। देवनानी की बिरला से संसदीय विधायी मामलों, विधान सभा के आगामी सत्र के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा विधायी कार्यों की गुणवता को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। देवनानी ने संसदीय मामलों के संबंध में बिरला से मार्गदर्शन भी लिया। देवनानी ने बिरला को राजस्थान विधानसभा की वर्तमान गतिविधियों, नवाचारों और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों की विस्तार से जानकारी दी। देवनानी ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि राजस्थान विधान सभा अपनी स्थापना का अमृत महोत्सव मनायेगी। विधान सभा गठन के 75वें वर्ष में प्रवेश के साथ अमृत महोत्सव के शुभारम्भ की रूप रेखा तैयार की जा रही है। देश की श्रेष्ठ विधानसभाओं में शुमार राजस्थान विधान सभा को लोकतंत्र का जीवन्त स्थल बनाने के लिए नये कदम उठाये जा रहे है। बिरला से राजस्थान विधान सभा के सदन को पेपर लैस किये जाने के संबंध में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग

- देवनानी की बिरला से संसदीय विधायी मामलों पर चर्चा

किये जाने का अनुरोध किया। बिरला ने संबंधित अधिकारियों को राजस्थान विधान सभा के नेवा प्रोजेक्ट की कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए। बिरला ने देवनानी को नेवा प्रोजेक्ट के संबंध में लोकसभा से हर सम्भव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। देवनानी ने बिरला को राजस्थान विधान सभा परिसर में बनाई गई कारगिल शौर्य वाटिका की जानकारी दी।

देवनानी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर राजस्थान विधान सभा में कारगिल शौर्य वाटिका में वीरांगनाओं द्वारा पौधारोपण किया गया। बिरला ने राष्ट्र के शौर्य के लिए विधान सभा द्वारा किये गये इस नये कदम की सराहना की। 75 वर्षों के गौरवशाली डिजिटल म्यूजियम को प्रतिदिन लोग देखने आ रहे है प्रतिदिन आमजन बढी संख्या में देखने आते हैं। उन्होंने इतिहास को रेखांकित करते हुए निकट भविष्य में आयोजित होने वाले विधानसभा से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी बिरला से साझा की।

# मुख्यमंत्री ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

- जैसलमेर के फूसासर में 765 के.वी. में स्थापित होगा विद्युत उपकेन्द्र

सरकार द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले की भणियाणा तहसील के फूसासर में 765 के.वी. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा यह विद्युत उपकेन्द्र 80 हैक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह निर्णय पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस उपकेन्द्र की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा आमजन को सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

# भाजपा रक्षाबंधन पर्व को सेवा, संगठन और समर्पण के रूप में मनाएगी

**जयपुर।** भारतीय जनता पार्टी आगामी 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन पर्व को जनसहभागिता, संगठनात्मक सहभागिता एवं सामाजिक समर्पण के साथ भव्य रूप में मनाने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता ''रक्षा का यह पर्व, सामाजिक एकता और सेवा का अवसर'' के मूलभाव के साथ जिलों, विधानसभाओं और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएंगे।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान संयोजक मुकेश दाधीच ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक जिला महामंत्री एवं महिला मोर्चा की दो पदाधिकारी संयोजक व सह-संयोजक के रूप में कार्यक्रम का संचालन करेंगी।

**8 अगस्त को सम्मान व समर्पण दिवस:**

इस दिन पार्टी कार्यकर्ता ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालयों, सरकारी व निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों सहित सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। बहनों द्वारा तिलक, राखी एवं मिष्ठान वितरण कर यह संदेश दिया जाएगा - आप हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। स्थानीय मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेवा भावना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

9 अगस्त को संगठनात्मक एकता व परिवार दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता इस दिन अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार - एक सूत्र में बंधा, संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव को सशक्त करेंगे।

10 अगस्त को सेवा व सामाजिक सद्भाव दिवस को भाजपा कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों को राखी भेजेंगे या उनके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। साथ ही कच्ची बस्तियों, मजदूर बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ियों और घुमंतू समाज के बीच जाकर राखी व मिठाई वितरित की जाएगी। यह दिन ''रक्षा का धागा, सम्मान और अपनत्व का संदेश'' लेकर सेवा और संवेदना का उत्सव बनेगा।

यह आयोजन सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा एवं मंडल स्तर पर आयोजित होंगे। पूर्व तैयारी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।

भाजपा का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन-जन तक पहुँचाना है।

रक्षा सूत्र से बंधेगा भारत, एकता, सेवा और संस्कारों के साथ - यही है इस कार्यक्रम की मूल भावना।


*In Loving Memory of*
Prof Meena Mathur

With heavy hearts, we share the news of the passing of our beloved Meena (Chiku), daughter of Lt Shri CBL Mathur and Lt Dr Tara Mathur

*Pushpa Shradhanjali*
will be held at
**Dharmarth Sansthan Hall**
Shiv Marg, Bani Park, Jaipur
between 4 and 5 pm, on August 7th, 2025

Sisters: Rekha Bhatnagar, Renu Consul, Beena Mathur, Reena Mathur; Family, Friends and Students

**RSVP:** 9899760139 (Radhika), 9828060790 (Ruchika), 9313336404 (Mayank), 9928499071 (Gaurav)


# शिक्षा के साथ संस्कारों की सीख दे रहा है गायत्री परिवार: दिलावर

**जयपुर।** किरण पथ, मानसरोवर स्थित गायत्री वेदना निवारण केंद्र परिसर में मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रवेशोत्सव- 2025 बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। उन्होंने मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गायत्री परिवार के इस विद्यालय ने बहुत कम समय में अच्छी तरक्की की है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी प्रदान कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय का शुभारंभ मेरे द्वारा हुआ था तथा आज प्रवेश उत्सव भी मेरी उपस्थिति में हो रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंन कहा कि गायत्री परिवार सामाजिक एवं राष्ट्रिहत के कामों में सदा अग्रणी रहता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि गायत्री परिवार सदैव समाज एवं राष्ट्र के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजकीय विद्यालय में बड़ी तेजी से नामांकन मे वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गुणात्मक प्रयास एवं नवाचारों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। बच्चों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ शिक्षा मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। शिक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की।

गायत्री परिवार के मां भगवती विद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों का प्रवेश उत्सव मनाया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी एवं राजस्थान जोन समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि यह विद्यालय गायत्री परिवार द्वारा निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में बच्चों को पाठ्य सामग्री, पोशाक एवं आवश्यक सुविधाएं गायत्री परिवार एवं समाजसेवी भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड 69 पार्षद आशीष शर्मा, वार्ड 70 के पार्षद रामावतार गुप्ता, वार्ड 72 के पार्षद पारस जैन तथा भाजपा मानसरोवर मंडल अध्यक्ष विपिन सिंघल उपस्थित रहे। ट्रस्टी सतीश भाटी, डॉ. प्रशांत भारद्वाज, केंद्र के व्यवस्थापक आर. डी. गुप्ता ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया।


राष्ट्र से करें प्यार,
स्वदेशी वस्त्रों को करें स्वीकार
परिवार की शान बढ़ाये, परम्परा, संस्कृति और विरासत का अहसास कराएं
RHDC हर मौसम में रखें ख्याल
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 25% की विशेष छूट
बुनकरों एवं दस्तकारों द्वारा तैयार वस्त्रों का विशाल संग्रह
- प्रिंटेड जेंट्स शर्ट और कुर्ते
- प्रिंटेड गुदड़ी, दरियां, जालौरी, बीकानेरी खेस
- कोटा डोरिया जरी, प्रिंटेड सॉडी, स्टोल और दुपट्टे
- बगरु/सांगानेरी प्रिंटेड साड़ियां, ड्रेस मेटेरियल
- मैरिनो लोई, शॉल
- जयपुरी रजाई, दोहर
- टेबल कवर और कुशन कवर
- सांगानेरी, बगरू और बाड़मेरी प्रिंटेड बैडशीट
- प्रिंटेड पर्दे, हैण्डलूम तौलिये और अन्य बहुत कुछ

उत्पादों की विशेषताएँ
- स्वदेशी वस्त्र
- पक्के रंग
- धुलाई में आसान
- पर्यावरण अनुकूल
- ज्यादा चले
- आकर्षक रंग और डिजाइन
- उत्पादों में विविधीकरण

राजस्थान संवाद
राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय एवं शोरूम :''हाथकर्घा भवन'' चौमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर-302001
0141-2371109 / 2361533 / 9773349080 rshdc@rajasthan.gov.in